फा.सं.जेड-14014/1/2021-जीसी (ई-3010921)
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011
दिनांक: 17.02.2021

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: जनवरी, 2021 के दौरान भूमि संसाधन विभाग के प्रमुख कार्यकलापों का मासिक सार।

अधोहस्ताक्षरी को जनवरी, 2021 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

अनुलग्नक: यथोक्त।

अर्जुन राणा

(अर्जुन राणा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
6. सचिव, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
7. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रायल, नई दिल्ली।
11. सचिव, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. सचिव, खान मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. सचिव, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. सचिव, व्यय विभाग, नई दिल्ली।
18. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
19. सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
20. सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
22. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीया ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के निजी सचिव।

जनवरी, 2021 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और मुख्य कार्यकलापों का मासिक सार

सैन्य गैरीसन तथा विभिन्न सैन्य टुकड़ियों की स्थापना के लिए यॉर्नी-II, जिला पश्चिम सियांग, अरूणाचल प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के लिए रक्षा मंत्रालय को दिनांक 27.01.2021 को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खंड (ड.) के उप-खंड (V) के तहत "समुचित सरकार" अधिसूचित किया गया।

डीआईएलआरएमपी का 3 वर्षों (01.04.2021 से 31.03.2024) के लिए विस्तार के लिए ईएफसी ज्ञापन को आईएफडी द्वारा अनुमोदित किया गया तथा 3 नए घटकों अर्थात (i) जिला स्तर पर आधुनिक अभिलेख कक्ष (ii) भूमि अभिलेखों के साथ आधार संख्या का समेकन (iii) राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (ई-आरसीएमसीएस) के साथ भूमि अभिलेखों के एकीकरण को शामिल करने के साथ माननीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया। इसे नीति आयोग तथा संबंधित मंत्रालयों को उनके टिप्पणियों/विचारों के लिए परिचालित किया गया है।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के विभिन्न घटकों की प्रगति की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

(i) 5,98,290 गांवों के भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा किया गया।

(ii) 4861 उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों के पंजीकरण के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा किया गया।

(iii) 1,09,10,562 भूकर मानचित्र / एफएमबी/टिप्पन के डिजिटलीकरण का कार्य पूरा किया गया।

(iv) 3924 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों के साथ भूमि अभिलेखों के एकीकरण का कार्य पूरा किया गया।

(v) 2162 तहसीलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना का कार्य पूरा किया गया।

भूमि संसाधन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन पहल (आईडब्ल्यूएमआई) द्वारा 07.01.2021 को वर्चुअल मंच पर आयोजित चर्चा में भाग लिया, तथा डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई की स्कीम के तहत वर्षासिंचित तथा अवक्रमित भूमि के विकास पर प्रकाश डाला।

सचिव (भूमि संसाधन) ने 03 जनवरी, 2021 को डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत तापीन तथा गोला (झारखंड में) वाटरशेड परियोजनाओं का दौरा किया तथा प्रगति की समीक्षा की; जबकि अपर सचिव (एलआर) ने संबंधित संयुक्त सचिव के साथ हैदराबाद का दौरा किया तथा डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के तहत, कुल 6382 परियोजनाओं {8214 (स्वीकृत) – 1832 (राज्यों को अंतरित) में से अब तक, 4743 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। 1000 करोड़ रुपए के संशोधित आबंटन की तुलना में 777.42 करोड़ रुपए की संचयी राशि के साथ जनवरी, 2021 में 123.06 करोड़ रुपए जारी किए गए।

*****